Ban on Export of Jute Goods to Saudi Arabia

1058. SHRI DHULESHWAR MEENA: *Will the Minister of TEXTILES* be pleased to state:

(a) whether the Government of India have examined the legal implications of the West Bengal Government's move to ban lawful export of jute goods to Saudi Arabia, when it had no objection to their export to Syria;

(b) whether the State Government is competent to over-ride rules and regulations set by the Centre particularly when Industry and trade involved fall under Schedule I of the Industrial Policy Resolution;

(c) whether Government have assessed the loss of foreign exchange as this incident might result in future business in export of jute products to the entire Gulf region; if so, what is their reaction thereto; and

(d) in what manner the issue is ultimately proposed to be resolved?

THE MINISTER OF TEXTILES AND FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI HUKUMDEO NARAYAN YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d) An assessment is being made and a Report on this will be laid on the Table of the House.

Accident due to Gas Leakage in Tisco Owned Colliery in Dhanbad and at the Steel Plant at Jamshedpur

1059. SHRI RAM AWADHESH SINGH: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that gas leakage accidents have taken place in TISCO owned Colliery in Dhanbad and Steel Plant at Jamshedpur repeatedly in the recent past;

(b) whether any enquiry committee has been set up to look into the matter and if so, the details thereof; and

(c) what steps are being taken to take action against the TISCO management for the deaths of more than fifty persons in a fire accident on the 3rd March, 1988?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI ASHOKE KUMAR SEN): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House after the information is received.

मैसर्स गोल्डन एन्टरप्राइजेज का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा

1060. श्री राम अवधेश सिंह : क्या वित्त मंत्री 24 मई, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1758 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में राष्ट्रीय बीमा कम्पनी के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मैसर्स गोल्डन एंटरप्राइजेज, दानापुर के बीमा के संबंध में एक स्पष्ट रिपोर्ट तत्कालीन वित्त मंत्री को लिखे इस आशय के एक पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कर लेने के बाद ही भेजी गई थी कि बाढ़ का जोखिम भी उसमें शामिल है, परन्तु कलकत्ता स्थित मुख्यालय में इस रिपोर्ट को दबा दिया गया ;

(ख) क्या सरकार उस जांच रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का और बाढ़ से होने वाले नुकसान तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर किए गए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा निक्षेप

1061. **श्री रणजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1990 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में किये गये कुल निक्षेपों में से 41.5 प्रतिशत निक्षेप देश के 13 शहरों में किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान इन शहरों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितनी ऋण-राशि दी गई थी ;

(ग) इस अवधि के दौरान दी गई यह ऋण राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई कुल ऋण राशि का कितना प्रतिशत थी ;

(घ) क्या सरकार बैंकों द्वारा अति सीमित क्षेत्र में अधिकांश ऋण देने की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सितम्बर, 1990 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 13 प्रमुख शहरों (बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे, कानपुर, चंडीगढ़, पटना और बड़ोदरा) में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां 75,392 करोड़ रुपए थी जो अखिल भारतीय बैंक जमाराशियों का 41.5 प्रतिशत बैठती है ।

(ख) सितम्बर, 1990 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार उक्त 13 शहरों में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं द्वारा दिये गये ऋण 58,891 करोड़ रुपए के थे ।

(ग) उपरोक्त 13 शहरों में बकाया ऋण राशि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के कुल ऋण राशि का 50.1 प्रतिशत बैठता है ।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि ऋण वितरण में विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाए और कमी वाले क्षेत्रों में सभी उत्पादक और अर्थक्षम प्रस्तावों को ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के कारगर कदम उठाये जाएं। बैंकों की अपनी-अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करने के अनुदेश दिये गये हैं ।

देश में चल रहे विदेशी बैंकों में जमा राशि और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि का अनुपात

1062. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1990 के अंत तक देश में चल रहे विदेशी बैंकों में जमा राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि की तुलना में अधिक थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कोई विशेष हिदायतें जारी की हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) 28 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंको और भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों